

00000

- एक राष्ट्र-एक चुनाव के बारे में गठित कोविंद समिति ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी-दो चरणों में चुनाव करने की सिफारिश की।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पेपर लीक को लेकर गठित एसआईटी टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की।
- केन्द्र सरकार ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए 9 सौ 72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदेश में गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू।

00000

एक राष्ट्र-एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट सौंपी। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र-एक चुनाव आकांक्षी भारत के लिए मुख्य बिन्दु है। मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद उच्च स्तरीय समिति ने देशभर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाएंगे। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों का तालमेल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ इस तरह से किया जाएगा कि नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बाद सौ दिन के अन्दर करा लिये जाएं। समिति ने सह सिफारिश भी की है कि सरकार की सभी त्रि-स्तरीय व्यवस्था के लिए चुनाव में एक ही मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

00000

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में पहली बार मतदान करने वाले उत्साहित युवा मतदाताओं का एक वीडियो साझा किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि पूरे देश के युवा मतदाता कह रहे हैं मेरा पहला वोट देश के लिए।

00000

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पेपर लीक को लेकर गठित एसआईटी टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ अब तक की गयी कार्रवाई और जांच के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। करीब दो घंटे चली इस बैठक में पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, एसओजी और एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक वी. के सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वी.के. सिंह ने कहा कि पेपरलीक में संलिप्त सभी लोग जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि एसआई पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई से आम जनता में एक अच्छा संदेश गया है। श्री सिंह ने कहा कि कार्रवाई के बाद आम लोगों की तरफ से एसओजी को विभिन्न जानकारी मिल रही है, जिन पर आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि अनुसंधान जारी है।

00000

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुड गवर्नेन्स का बेहतरीन मॉडल स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के अधिकारी जन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उनका शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इधर विभिन्न जिलों में भी जिला कलक्टरों ने लोगों को समस्याओं से राहत देने के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर जन सुनवाई की। सर्वाइमाधोपुर, बूंदी और दौसा जिलों के कलक्टरों ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्यायें सुनी और विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया तथा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन से संबंधित जनसमस्याओं और परिवेदनाओं का प्राथमिकता से समाधान करें।

00000

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी को

समान अधिकार मिलेंगे, क्योंकि अब वे भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिससे किसी की नागरिकता छीनी जा सके।

00000

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइटों, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें ड्रीम्स फिल्मस, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, प्राइम प्ले और अनकट अड्डा शामिल हैं। यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों में अधिकतर अंश अश्लील और महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने वाले पाये गये हैं।

00000

केन्द्र सरकार ने राज्य में 31 विशेष सड़कों और स्टेट हाईवे को चौड़ा बनाने और उनके विकास के लिए 9 सौ 72 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सात रेलवे ऑवरब्रिज, अण्डर ब्रिज और फ्लाई ओवर बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क और आधारभूत संरचना निधि— ब्थ सेतुबंधन योजना के अंतर्गत 3 सौ 84 करोड़ 56 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

00000

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 9 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों के निर्माण से बॉर्डर एरिया से जुड़े गांवों व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा बल की चौकियों तक सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी। इससे ग्रामीणों और सैन्य बलों का आवागमन सुगम होने के साथ लॉजिस्टिक्स की समयबद्ध आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।

00000

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने घरेलू तथा विश्व में वैज्ञानिक उपलब्धियों में भारत की भूमिका की सराहना की है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान-प्रौद्योगिकी पैनोरमा के एक दशक शीर्षक की रिपोर्ट जारी करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने चन्द्रयान और आदित्य एल-1 जैसी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमता की बात कही। डॉ. सिंह ने भारत के गगनयान मिशन पर गर्व करते हुए कहा कि इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की प्रसिद्धि ओर बढ़ायी है। उन्होंने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के उत्थान की भी सराहना की। श्री सिंह ने इन क्षेत्रों की सफलता का श्रेय नवाचार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित सरकारी नीतियों को दिया।

000000

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदेश में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। झालावाड के चौमेला मंडी से इसकी शुरुआत हुई। कोटा संभाग में कल से समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद भी शुरू हो जायेगी। इसके लिए ईकृमित्र के माध्यम से पंजीकरण शुरू हो गया है। राजफेड के महाप्रबंधक निरंजन सिंह राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया कि गेहूं की खरीद 10 मार्च से जारी है। कल से समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद कोटा संभाग से शुरू होगी। इसके लिए कुल एक हजार 40 खरीद केंद्र बनाये गये हैं। इसके बाद एक अप्रैल से पूरे राज्य में समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद एक अप्रैल से शुरू हो जायेगी। इसके लिए किसान 22 मार्च से ईकृमित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

00000

झुंझुनूं जिले के शहीद महेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनासर में आज जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने निशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, कोचिंग तथा डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिल सकेगी। सीबीईओ अनुसुइया सिंह ने बताया कि इस नवाचार से विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा मिलेगी।

-----

00000

लोकसभा आम चुनाव- 2024 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की पहल पर व्यापक स्तर पर स्वीप गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत 17 मार्च को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर राज्य के सभी 51 हजार 756 मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम, क्रमांक एवं मतदान केन्द्र आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु 17 मार्च को विशेष अभियान का आयोजित किया जाएगा।

0000